AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

शिक्षा और समुदायों को जोड़ती एनईपी 2020

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. किरण वर्मा
हिंदी विभाग
संत गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला
एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय
देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

प्राचीन काल से ही जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब से ही शिक्षा भारतीय समाज की बुनियादी आधार रहीं है। भारत के औपनिवेशीकरण से पहले अनौपचारिक ढाँचे वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रणाली के अंतर्गत समाज से संवाद एवं ज्ञान और इसके उपयोग के बीच संबंध की ज्यादा संभावना थी। भारत में उच्चतर शिक्षा नालंदा और तक्षशिला के समय में ज्यादा समग्र और समाज से जुड़ी हुई थी। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित है क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा, प्रणाली का ढाँचा औपचारिक था और भारतीय शिक्षा के विकास में इसका बहुमूल्य योगदान है। विश्वविद्याल, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर शिक्षा के ढांचे का निर्माण एवं विकास भारत में इसी प्रणाली के अनुसार हुआ है।

मुख्य शब्द

शिक्षा, बुनियादी औपचारिक, अनौपचारिक, गुरुकुल, समुदाय, समाज. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय.

प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है यही कारण है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देश की आरंभिक शिक्षा प्रणाली में नीतियों पर आधारित है बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा और विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच समानता पर बल दिया गया है। पहुँच, गुणवत्ता और न्यायसंगता हासिल करने के लिये दोनों नीतियाँ नियामक ढांचों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में सफल रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ–साथ अनेक चुनौतियां भी सामने आयी हैं। इसकी उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान दिये जाने से शिक्षा और अधिक ज्ञानोपयोगी बन गयी। व्यक्ति एक समाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसलिए सामुदायिक भागीदारी शिक्षा को समाज से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समुदाय अपने स्वामित्व का प्रयोग शैक्षिक प्रयासों के विस्तार के लिए करें और वहीं दूसरी तरफ शैक्षिक संस्थान अपने कार्यक्रम और सेवाओं को समाज के सशक्तीकरण में लगायें जिससे शिक्षा और समुदाय के बीच अंतर–संबंध विकसित होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यालय विकास और जो निगरानी समितियाँ होती हैं वह स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटीज (एसडीएमसी) में भागीदारी के द्वारा समुदाय शैक्षिक प्रयासों तक अपने स्वामित्व का विस्तार निर्वहन करता है। वहीं शैक्षणिक संस्थान एनएसएस, एनसीसी, रेडक्रास एवं अन्य ऐच्छिक प्रयासों के उनसे माध्यम से समुदाय के साथ काम करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2000 का लचीलापन एवं स्वायत्ता समुदायिक भागीदारी को शिक्षा का अंतर्निहित तत्त्व बनाती है, क्योंकि संस्थागत स्तर पर सामुदायिक भागीदारी का लचीलापन अधिक अवसर प्रदान करता है। संस्थानों को स्वायत्तता से ताकत मिलती हैं। एनईपी 2020 के द्वारा हम, शिक्षा, सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस नीति में शिक्षा में समुदाय की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका को स्पष्ट किया गया है। आंगनबाड़ियों की शिक्षा

को समुदाय की प्रत्यक्ष भूमिकाओं के दायरे में लाना, शिक्षा को संपूर्ण और बहुविधेयक बनाना, विभिन्न स्तरों पर कौशल विकास को जोड़ना एवं अनुभव के द्वारा ज्ञानार्जन की ओर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। शिक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम से स्थानीय कौशलों को जोड़ना तथा समुदाय समाज एवं समुदाय को प्रभावित करने वाले सार्थक अनुसंधान पर ध्यान आकर्षित करना है।

स्कूली शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता

एनईपी, 2020 में एक ऐसी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की संकल्पना की गई है जिसमें कल्याणकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी हों। वास्तव में समुदाय स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग है। स्कूली शिक्षा के सजाने संवारने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गाँव के विद्यालय प्रभावी रूप से काम तभी करते हैं जब स्थानीय समुदाय सक्रिय होकर स्कूलों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) के विषय में एनईपी 2020 में कहा गया है कि आंगनबाड़ियां पूरी तरह से समेकित परिसर या समूह होंगी, जिसमें बच्चों के पालकों, अभिभावकों और शिक्षकों को स्कूल परिसर के कार्यक्रमों में संक्रिय भागीदारी के लिये आमंत्रित किया जायेगा। अब तक आँगनबाड़ियों के द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण आहार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें शिक्षा से जोड़े जाने से आँगनबाड़ियों का विस्तार होता है तथा अभिभावकों, पालकों व समुदाय को जरूरी पोषण, स्वास्थ्य सेवा व बाल शिक्षा प्रदान कराने में सक्षम भूमिका निभाती है।

स्कूल परिसर आस–पास के विद्यालयों को एक समूह में एकत्रित करता है। इससे वे अपने ज्ञान तथा शिक्षकों एवं भौतिक संसाधनों को साझा करते हैं। इससे बड़ा लाभ आस–पास के समुदायों को होगा। विस्तृत आधार वाले स्कूल परिसरों एवं समूहों से स्थान और स्थिति के अनुरूप नवचार को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय प्रबंधन समितियाँ विशेषज्ञ स्कूल समूहों के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मेदारी उठा सकते हैं।

गैर–सरकारी जनकल्याणकारी संगठनों को स्कूल बनाने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे स्कूलों के प्रबंधन, विकास, संसाधनों, विभिन्न प्रक्रियाओं और विद्यालय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस नीति के अंतर्गत ज्ञानार्जन को प्रभावी बनाने व बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्व छात्रों तथा स्वयंसेवियों की भागीदारी का सुझाव दिया गया है।

एनईपी 2020 में 'सामाजिक चेतना का केंद्र खोलने का सुझाव दिया गया है इससे स्कूल की अप्रयुक्त आधारभूत संरचना क्षमता का उपयोग हो सके। केंद्र समुदाय के लिये सामाजिक, बौद्धिक और स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। इन सभी गतिविधियों से सामाजिक एकता को प्रोत्साहन मिलेगा।

उच्चतर शिक्षा में सामुदायिक जिम्मेदारी

नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और सामुदायिक दायित्व निर्वहन के लिये अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।

उच्चतर शिक्षा में सामुदायिक दायित्व सौंपने सिद्धांतों और व्यवहार के बीच दूरियाँ मिटती है इसलिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों और समुदायों के बीच गहरा संवाद होना अतिआवश्यक है। शिक्षा और समुदाय एक सिक्के के दो पहलू है अर्थात् दोनों एक–दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार शिक्षा समाज की समस्याओं का हल ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ठीक उसी प्रकार समाज भी पाठ्यक्रम विकास शिक्षण और ज्ञान–अर्जन वं अनुसंधान की गतिविधियों में शिक्षण संस्थानों की सहायता करती है।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य सिफारिश उच्चतर शिक्षा को विस्तृत और समग्र बनाने वाली आधारभूत संरचना है जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा के बहुविषयक संस्थान में बदल जायेंगी। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जिम्मेदारी के साथ स्नातकोत्तर और स्नातक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम संचालित करेंगे। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली– च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) पाठ्यक्रमों के विविधतापूर्ण विषयों को जन्म देगी। ज्ञान अध्ययन के आधार को विस्तार देने के लिये सामुदायिक सेवा, पर्यावरण एवं मूल्य तथा नैतिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों को संचालित करने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता प्रबंधन, जैविक संसाधन, वन और वन्य जीव संरक्षण और एवं संवहनीय विकास जीवन शैली जैसे क्षेत्रों

में परियोजनाओं का निर्माण करने का सुझाव प्रस्तावित है।

मूल्य आधारित शिक्षा में मानवीय, नैतिक शिक्षा, संवैधानिक और वैश्विक मानव मूल्यों व जीवन कौशल का विकास करना शामिल हैं। छात्रों को व्यवसायों, स्थानीय उद्योगों, कलाकारों और शिल्पकारों के साथ प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जायेंगे इसके साथ ही वे अपने और अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ अनुसंधान का प्रशिक्षण ले सकेंगे। खेल, संस्कृति, पर्यावरण क्लबों और सामुदायिक सेवा परियोजनाओं के द्वारा व्यवहारिक रूप से सक्रियता से जुड़ सकेंगे। एनईपी 2020 वैश्विक नागरिकता शिक्षा– ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन (जीसीईडी) के अनुरूप छात्रों के सशक्तिकरण की सिफारिश करती है।

एनईपी 2020 लागू करने की दिशा में प्रयास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय ग्रांटस कमीशन (यूजीसी) ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क विकसित किये हैं. इसका विशेष उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। 'उन्नत भारत अभियान' के अंतर्गत छात्रों के ग्रामीण समुदाय से जोड़ने के लिये कोर्स और पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् को सामाजिक जिम्मेदारी देने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स तैयार करने और उन्हें 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर चलाने का दायित्व सौंपा है। संस्थानों में सामुदायिक भागीदारी का क्रियांन्वयन सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के संचालन, शिक्षण और ज्ञानार्जन, अनुसंधान तथा सांस्थानिक विकास में समुदायों को शामिल करने की बात कही गयी। सामुदायिक भागीदारी के वास्तविक रूप से बदलने के लिये संस्थानों के पास निम्नलिखित विकल्प दिये गये हैं:

1. सरकार से मिलने वाले दिशा निर्देशों को लागू करें।
2 सरकार और अन्य संस्थानों से दिशा निर्देश नहीं मिलने की स्थिति में भी वे नीति की भावना के अनुरूप उसे लागू करें। समूह का गठन करें, और हितधारकों को साथ लेते हुए उन्हें लागू करें।
3. एनईपी 2020 से भी आगे बढ़कर समुदाय के संस्थान के नजदीक लाने के लिये नये तरीके अपनाने चाहिए।
4. नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 – इस नई शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया है इसका मुख्य उद्देश्य वयस्कों को अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के अवसर प्रदान करना है जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य सीखने का इको सिस्टम बनाकर वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
5. नई शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिन्दु 'बहुविषयक और समग्र शिक्षा है। दूसरी ओर कठोर, पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन परीक्षा और उसके अधिगम के आकलन को योगात्मक तरीकों से अपनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये छात्रों की खोज और सीखने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य चरण 5+3+3+4 यहाँ पर पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना का आयु के आधार पर कक्षा वार विवरण दिया गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक, विकासात्मक चरणों पर ध्यान दिया जाये।
7. 13 सितम्बर 2023 से राज्य सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 को अक्षरशः लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को एनईपी के (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1 के अंतर्गत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिये नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये हैं जिसके अंतर्गत अब स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घण्टे ही पढ़ाई होगी।
8. बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
9. एक नये राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना।
10. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रगति की निगरानी पाँच विषयों के माध्यम से की जाएगी अर्थात शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा डिजिटल लर्निंग उद्योग संस्थान, शैक्षणिक अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारतीय ज्ञान प्रणाली।
11 भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सामाजिक संपर्क की जरूरत को शिक्षा के द्वारा पूरा करने की कोशिश की गयी है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये गैर–सरकारी संगठनों, सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत ज्ञानार्जन के तार्किक लक्ष्य को भी स्पष्ट किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसमें सिद्धांतों का उपयोग से और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इनके व्यावहारिक प्रयोग समझ सकें।

संदर्भ सूची

1. कुलश्रेष्ठ, कमल (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (विशेषांक). *योजना,* मासिक पत्रिका, फरवरी 2022, वर्ष – 66 अंक – 2 पृ. 35–37।
2. www.publicationdivision.nic.in, Accessed on 12/03/2026.
3. गुप्ता, एस. पी. (2006) *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 5।

––==00==––